

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 09 फरवरी, 2011

विषय-मा० उच्च न्यायालय नैनीताल कार्यालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-11/XXXVI(1)-एक/10-234/2001 दिनांक 21 जनवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यालय हेतु सृजित 426 एवं शासनादेश संख्या-148/XXXVI(1)-एक/2010-234/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2010 के द्वारा सृजित बेंच सेक्रेटरी ग्रेड-1 के 03 पदों (कुल 429 अस्थायी पदों) की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-234/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 02.05.2001, शासनादेश संख्या-22-एक(2)/न्याय विभाग/03 दिनांक 27.08.2003, शासनादेश संख्या-8 एक((2)/न्याय विभाग /2004, दि० 17.01.04, शासनादेश संख्या-25-एक((2)/न्याय विभाग/2004, दिनांक 06.08.04, शासनादेश संख्या-181/XXXVI(1)-एक/2006-234/2001 दिनांक 13.12.2006 शासनादेश संख्या-67-एक (1)/XXXVI(1) 2008 दिनांक 03 मार्च, 2008 एवं शासनादेश संख्या-230/XXXVI(1)/2009-234/2001 दिनांक 11 अगस्त, 2009 एवं शासनादेश संख्या-148/XXXVI(1)-एक/2010-234/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2010 द्वारा किया गया था।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00" की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अर्न्तगत प्रसारित किये जा रहे हैं।


4- उक्त के साथ ही वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-118 (1)/XXVII (7)/2006, दिनांक 31 अगस्त, 2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त सृजित पदों में से 05 वर्ष पूर्ण करने वाले पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-25(1)XXXVI(1)/2011-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-5/ कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव।